(b) what is the actual demand of the Rajasthan Government;

(c) what are the names of major projects for which allocation has been made in the Eighth Five Year Plan and what are the names of other projects which have been left out; and

(d) what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H.R. BHARDWAJ) : (a) An aggregate Public Sector outlay of Rs. 412000 crores has been proposed in the Eighth Five Year Plan for developmental projects in the country. As regards Rajasthan, a total outlay of Rs. 11500 crores has been fixed.

(b) The Government of Rajasthan had proposed an outlay of Rs. 10450.72 crores for the Eighth Plan in their plan document.

(c) and (d) The outlays are approved by Planning Commission Development-head-wise/sub-head-wise and not project-wise.

Request of Rajasthan Government for clearance of pending Projects

596. SHRI B.L. PANWAR : Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) whether Government of Rajasthan has requested the Central Government to give early clearance to various pending projects of Rajasthan; and

(b) if so, the details thereof alongwith the reaction of the Central Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H.R. BHARDWAJ) : (a) and (b) Jaisamand Modernisation Scheme estimated to cost Rs. 12.40 crores is pending for investment approval in the Planning Commission. The scheme is under examination in the Planning Commission.

Revision of outlays of States due to Inflation

597. DR. SANJAYA SINH : Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) what are the names of the States whose outlays for the Eighth Five Year Plan have been agreed to between the State Government concerned and the Planning Commission:

(b) whether these outlays are subject to any revision during the Eighth Five Year Plan period due to inflation; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H.R. BHARDWAJ) : (a) The Eighth Plan outlays of all States have been finalised.

(b) and (c) The Eighth Plan outlays are with reference to 1991-92 prices. However, the operational plans are the Annual Plans which will be at current prices.

उत्तर प्रदेश में योजनाओं की प्रगति पर निगरानी

598. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही योजनाओं की यह देखने के लिए निगरानी नहीं कर रही है कि वहां पर योजनाओं का कार्यान्वयन ठीक तरह से हो रहा है अथवा नहीं; और

(ख) उत्तर प्रदेश की उन परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं जिनके संबंध में केन्द्र सरकार ने स्वयं ही जानकारी जुटाई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, नहीं । योजना आयोग में राज्य योजनाओं पर निगरानी रखने की एक पद्धति 1986 में आरम्भ

की गई थी। यह अभी भी चालू है; यद्यपि इसे अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इस पद्धति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की योजनाओं की भी निगरानी की जाती है।

(ख) किसी राज्य में महत्वपूर्ण विशिष्ट परियोजनाओं की निगरानी राज्य योजना के अन्तर्गत संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। तदनुसार उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं की निगरानी की जाती है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये निधियों का आवंटन

@599. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आलिया :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की उपलब्धियों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आबंटित की गई ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) (क) जी, नहीं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण या अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, समय-समय पर अंतरमंत्रालयी बैठकों में कार्यक्रम के तहत निष्पादित कार्य की समीक्षा की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के चार घटकों अर्थात्-ग्रामीण ईंधन लकड़ी खेती स्कीम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पोषाहार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आबंटनों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इन आबंटनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के शेष घटकों अर्थात् प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलआपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण स्वास्थ्य तथा उन्नत चूल्हों के लिए आबंटनों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम घटक	वर्ष 1992-93 के दौरान निधियों का आवंटन (लाख रु०)
(क) ग्रामीण ईंधन लकड़ी खेती स्कीम	2930.00
(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली	252627.00
(ग) पोषाहार	25646.73
(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण	14500.00
जोड़ :	295703.73

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 137, 28 अप्रैल, 1992 से स्थानांतरित।